- राज्य में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए विष्वस्तरीय प्रमाणीकरण पद्धति 'Credit based Evaluation System' एवं डिप्लोमा प्रथम वर्ष से अद्यतन सिलेबस लागू किया गया।
- राज्य में स्थापित केन्द्रीय संस्थान यथा आई०आई०टी० पटना एवं एन०आई०टी० पटना के अतिरिक्त भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर के परिसर में उपलब्ध 50 एकड़ भूमि पर **आई०आई०आई०टी० (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी)** की स्थापना एवं उसके संचालन का निर्णय लिया गया।
- **संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा-मेन्स (J.E.E.-Mains)** के मेधा के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में छात्रों का नामांकन लेने का निर्णय लिया गया।
- Apprentice Act. 961 के तहत राज्य सरकार के अधीन संचालित अभियंत्रण महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निक संस्थानों में राज्य के तकनीकी संस्थानों से उत्तीर्ण डिग्री एवं डिप्लोमाधारी छात्रों को उनके गुणवत्ता एवं व्यावहारिक ज्ञान में वृद्धि के साथ-साथ रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से एक वर्षीय अप्रेन्टिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई तथा प्रशिक्षण अवधि में डिग्रीधारी प्रशिक्षु को 15,000 रुपये प्रतिमाह एवं डिप्लोमाधारी प्रशिक्षु को रु0 10,000 रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

वर्ष 2020 से अबतक

- पूर्व से स्थापित 7 अभियंत्रण महाविद्यालयों (मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मोतिहारी, दरभंगा, गया, छपरा एवं नालन्दा) में केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज-III (Technical Education Quality Improvement Plan Phase-III) के क्रियान्वयन का कार्य किया गया।
- कोविड-19 संक्रमण के दौरान अभियंत्रण तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में पाठ्यक्रमों का संचालन ऑन-लाईन पद्धति से पूर्ण किया गया।
- अभियंत्रण तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के छात्र/छात्राओं के लिए Virtual Classroom Software (VCS) विकसित किया गया। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों के शिक्षकों द्वारा शाखावार/विषयवार/अध्यायवार ऑनलाईन क्लास के विडियो लेक्चर, नोट्स एवं प्रश्न इत्यादि अपलोड किये जाने का प्रावधान किया गया, जिससे छात्र/छात्राएं अपनी सुविधानुसार डाउनलोड कर अध्ययन कर सकेंगें।
- छात्र-छात्राओं को इंडस्ट्री की माँग के अनुरूप अपेक्षित 17 नये टेक्नोलॉजी यथा-साइबर सिक्यूरिटी, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डाटा साईंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग आदि क्षेत्रों में अभियंत्रण महाविद्यालयों के कुल 6,840 छात्र-छात्राओं को आई0आई0टी0, कानपुर के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा कुल 6,223 छात्र-छात्राओं को प्रारंभिक एवं उच्च स्तर का प्रशिक्षण भी आई0आई0टी0, कानपुर के माध्यम से दिया गया।
- राज्य के युवाओं को समुचित तरीके से दक्ष करने के उद्देश्य से सरकार के **7 निश्चय-2** से संबंधित **"युवा शक्ति, बिहार की प्रगति"** निश्चय के अन्तर्गत राज्य के सभी पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसके माध्यम से नए एवं उभरते तकनीक जैसे ड्रोन तकनीक, सोलर टेक्नोलॉजी, ऑप्टीकल फाईबर नेटवर्किंग, आर्टिफिसियल इंटेलीजेंस, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, रोबोटिक्स इत्यादि में उद्योग की माँग के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना की सहायता से सभी 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु Center of Excellence की स्थापना की गयी है। 44 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में से 11 Hub तथा 33 Spoke संस्थान के रूप में चयनित किये गये तथा सभी केन्द्रों पर प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है।
- **7 निश्चय-2** के तहत सभी अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में हिन्दी में तकनीकी शिक्षा का पठन-पाठन प्रारंभ कर दिया गया है।
- राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु **7 निश्चय-2** से संबंधित **"युवा शक्ति, बिहार की प्रगति"** निश्चय के अन्तर्गत राज्य में **बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालयों** की स्थापना की गयी।
- बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय का अस्थायी रूप से संचालन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के छठे तल में प्रारंभ कर दिया गया है। विश्वविद्यालय के स्थायी परिसर के लिए बस स्टैंड, मीठापुर में कुल 5 एकड़ भूमि शिक्षा विभाग, बिहार द्वारा आवंटित किया गया है।
- महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता को दृष्टिगत रखते हुए अभियंत्रण विश्व विद्यालय से सम्बद्ध सभी संस्थानों में नामांकन हेतु एक तिहाई सीटों को छात्राओं के लिए आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया।
- **इंदिरा गाँधी साईन्स कॉम्पलेक्स परिसर, पटना** में अवस्थित तारामंडल में आम जनों के लिए नियमित रूप से सौर मंडल, कॉसमॉस, स्पेस एवं गैलेक्सी तथा समुद्र के नीचे के एक्वेटिक लाइफ आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम के प्रदर्शन की व्यवस्था की गयी। तारामंडल के प्रोजक्शन सिस्टम के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन सहित सिविल, इलेक्ट्रिकल वर्क्स सहित अन्य कार्यों एवं ऑप्टिकल टेलिस्कोप के अधिष्ठापन का निर्णय लिया गया।
- इंदिरा गांधी साईन्स कॉम्प्लेक्स परिसर, तारामंडल, पटना के आधुनिकिकरण हेतु 6K, 2D/3D, Digital Pure RGB Lesers, Projection system, Space Gallery, Telescope का अधिष्ठापन कुल 41.88 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक तकनीक द्वारा किया जा रहा है, जो लगभग पूर्ण है।
- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग तथा बिहार कौशल विकास मिशन के संयुक्त पहल से CISCO के द्वारा Corporate Social Responsibility (CSR) के अन्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों के कुल 70,462 छात्र-छात्राओं का CCNA & IT-Essential (Cisco Certified Network Associate & IT-Essential) कोर्स में नामांकन किया गया, जिसमें से लगभग 19,987 छात्रों का CISCO द्वारा प्रमाणन किया गया।
- **दिनांक 15.06.2023 से विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग का नाम परिवर्तित कर विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग कर दिया गया है।**

Nov. 2024
Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा

बिहार को विकास की राह में अग्रणी बनाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य **'सतत् विकास'** को परिभाषित करते हैं। वर्ष 2005 में बिहार की कमान संभालते ही **माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार** जी ने राज्य का विकास, एक सुव्यवस्थित एवं बेहतर कार्ययोजना के साथ करने का निर्णय लिया। उनके द्वारा राज्य और राज्यवासियों की बेहतरी हेतु लिया गया हर निर्णय और कदम **ठोस, तर्कपूर्ण, न्यायसंगत और समय की मांग के अनुसार** रहा। लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही उनके जीवन में गुणवत्तापूर्ण सुधार करते हुए उन्हें बदलते समय के साथ दक्ष और सक्षम बनाने के ध्येय के साथ भी कार्य किया गया।

श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विभिन्न प्रक्षेत्रों के विकास के साथ ही विज्ञान एवं प्रावैधिकी के प्रक्षेत्र को भी बढ़ावा देने का काम किया गया। उन्होंने बिहार के विकास की जिम्मेवारी जब अपने हाथों में ली तो राज्य में विज्ञान एवं प्रावैधिकी तथा तकनीकी शिक्षा के संदर्भ में कार्य न के बराबर किए गए थे। युवाओं को दक्ष और सक्षम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। अन्य राज्यों की तुलना में समुचित संख्या में तकनीकी संस्थान मौजूद नहीं थे। उपलब्ध संस्थानों में गुणवत्ता का स्तर भी समय की मांग के अनुरूप नहीं था। इस चुनौती को श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भलीभांति पहचाना और उसमें सुधार करने का कार्य किया।

राज्य के औद्योगिक, सामाजिक, आर्थिक विकास तथा नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु **तकनीकी रुप से दक्ष मानव संसाधन को सुदृढ़ करने का काम** किया जा रहा है। इस विभाग के अंतर्गत **तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने तथा वैज्ञानिक शोध एवं सेवाओं के विस्तार** का कार्य जारी है। पूर्व में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अंतर्गत योजनाएं संचालित की गईं तथा वर्तमान में इसके स्वरुप का विस्तार करते हुए विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत योजनाओं का प्रभावी रुप से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

वर्ष 2005 से 2010

- पटना में बिड़ला प्रावैधिकी संस्थान, मेसरा की विस्तार शाखा की स्थापना की गयी तथा शिक्षण सत्र आरंभ किया गया।
- राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त निर्धन छात्रों को, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय डेढ़ लाख रु0 से कम हो, उन्हें भारतीय प्रावैधिकी संस्थान (आई0आई0टी0) में चयनित होने पर 50 हजार रूपये छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया गया।
- निजी क्षेत्रों में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु प्रोत्साहन नीति बनायी गयी।
- **भारतीय प्रावैधिकी संस्थान (आई0आई0टी0), पटना** की स्थापना की गयी। राज्य सरकार द्वारा इस हेतु भूमि एवं अस्थायी भवन परिसर की व्यवस्था की गयी, साथ ही स्थायी परिसर हेतु मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा में 500 एकड़ भूमि का अर्जन किया गया।
- National Institute of Technology (NIT), Patna के लिए 100 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गयी।
- गया, मोतिहारी और दरभंगा में वर्षों से बंद पड़े 3 इंजीनियरिंग कॉलेज का पुनः संचालन और चंडी में नये इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गयी। चारों इंजीनियरिंग कॉलेजों में वर्ष 2008-09 से शिक्षण सत्र प्रारंभ किया गया।
- मधेपुरा और सीतामढ़ी में दो नए इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना का निर्णय लिया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में सत्र 2008-09 से सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक गुलजारबाग, दरभंगा एवं छपरा में 50 सीटों के महिला छात्रावास के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया।

वर्ष 2010 से 2015

- राज्य के 23 जिले जहाँ पॉलिटेक्निक संस्थान नहीं है, वहाँ पॉलिटेक्निक संस्थानों की स्थापना हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की गयी।
- जमुई, सुपौल तथा कैमूर जिला में नये पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गयी।
- पूर्व से स्थापित राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में नये अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने की स्वीकृति दी गयी। अस्थावाँ (नालन्दा), लखीसराय, डिहरी ऑन सोन, कटिहार तथा वैशाली जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- राज्य के 38 जिलों में से 15 जिलों में सरकारी क्षेत्र में 18 पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित एवं संचालित किये गये। 04 जिलों यथाः-बांका, गया (टिकारी), मुंगेर तथा समस्तीपुर में नये पॉलिटेक्निक की स्थापना एवं उनमें प्रस्तावित भवनों के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी।
- पूर्व से स्थापित राजकीय महिला पॉलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर के लिए बियाडा द्वारा उपलब्ध कराये गए भूमि पर संस्थान के भवनों के निर्माण की योजना स्वीकृत की गयी।
- ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा द्वारा संचालित स्ववित्तपोषित वीमेंस इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दरभंगा को राज्य सरकार द्वारा अनुशंसा प्रदान की गयी तथा संस्थान में पठन-पाठन आरंभ किया गया।
- राज्य में आई0आई0आई0टी0 (इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) संस्थान की स्थापना हेतु नालन्दा जिला के हरनौत में 105 एकड़ भूमि चिह्नित की गयी।
- महान गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री आर्यभट्ट से संबंधित ऐतिहासिक स्थलों यथाः-खगौल एवं तारेगना को संरक्षित एवं विकसित करने के उद्देश्य से ASTRO-TOURISM परियोजना के लिए परामर्शी संस्थाओं के चयन की कार्रवाई की गयी।
- लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा में भवनों के निर्माण के साथ शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के पदों का सृजन कर वर्ष 2012-13 से 4 स्नातक स्तरीय अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में सत्र प्रारंभ किया गया।
- मुंगेर प्रमंडल के बेगूसराय में राजकीय पॉलिटेक्निक, बरौनी के परिसर में उपलब्ध 30 एकड़ भूमि पर राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय के भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया।
- विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पॉलिटेक्निक के शैक्षणिक संवर्ग, गैर- शैक्षणिक तकनीकी कर्मी संवर्ग तथा गैर-शैक्षणिक गैर-तकनीकी अन्य संवर्गों का प्रारूप नियमावली तैयार किया गया।
- राज्य के 9 प्रमण्डलों में से 6 प्रमण्डलों यथा-सारण, तिरहुत, दरभंगा, भागलपुर, मगध एवं पटना में सरकारी क्षेत्र में कुल 7 अभियंत्रण महाविद्यालय स्थापित एवं संचालित किये गये।

वर्ष 2015 से 2020

- विकसित बिहार के सात निश्चय से संबंधित **"अवसर बढ़े, आगे पढ़े"** निश्चय के तहत युवाओं को राज्य में तकनीकी शिक्षा के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु राज्य के प्रत्येक जिलें में अभियंत्रण महाविद्यालय तथा पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

  वर्तमान में सभी 38 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। सभी 38 पॉलिटेक्निक संस्थानों के भवन का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा बक्सर जिला को छोड़कर शेष 37 जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय के भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
- विभागाधीनस्थ अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक/ राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों (व्याख्याता के पद को छोड़कर) की नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा को समाप्त करने का निर्णय लिया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्राचार्यों की नियुक्ति की गयी।
- **बिहार स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर** के सुदृढ़ीकरण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।
- पटना में **डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी** की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निर्माण हेतु आर्किटेक्ट, प्रदर्श डिजाईनर एवं कन्टेन्ट डिजाईनर का चयन किया गया।
- वर्तमान में डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया।
- दरभंगा में तारामंडल-सह-विज्ञान संग्रहालय के स्थापना की स्वीकृति दी गयी तथा प्रस्तावित भवनों के वास्तुविदीय आरेखन पर सहमति प्रदान की गयी।
- दरभंगा जिले में **तारामंडल-सह-विज्ञान** संग्रहालय का निर्माण 164.31 करोड़ रुपये की लागत से किया गया एवं वर्तमान में आम जन के लिए संचालित है।
- गया में साइंस सेन्टर की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी। **उप-क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र एवं नव-प्रवर्त्तन केन्द्र,** गया का निर्माण 5.99 करोड़ रुपये की लागत से किया गया एवं वर्तमान में आमजन के लिए संचालित है।